G20 Study Material (Hindi)

पृष्ठभूमि

20 के समूह (जी20) में 19 देश शामिल हैं (अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, संयुक्त राष्ट्र साम्राज्य, और संयुक्त राज्य अमेरिका) और यूरोपीय संघ। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, विश्व व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जी20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है और सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक वास्तुकला और शासन को आकार देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
G20 का कोई स्थायी सचिवालय या कर्मचारी नहीं है। इसके बजाय, G20 की अध्यक्षता सदस्यों के बीच सालाना बदलती रहती है और देशों के एक अलग क्षेत्रीय समूह से चुनी जाती है। इसलिए 19 सदस्य देशों को अधिकतम चार देशों वाले पांच समूहों में विभाजित किया गया है। अधिकांश समूह क्षेत्रीय आधार पर बनते हैं, जिसका अर्थ है कि एक ही क्षेत्र के देशों को आमतौर पर एक ही समूह में रखा जाता है। केवल समूह 1 (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका) और समूह 2 (भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की) इस पैटर्न का पालन नहीं करते हैं। समूह 3 में अर्जेंटीना, ब्राज़ील और मेक्सिको शामिल हैं; समूह 4 में फ़्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं; और समूह 5 में चीन, इंडोनेशिया, जापान और कोरिया गणराज्य शामिल हैं। यूरोपीय संघ, 20वां सदस्य, इनमें से किसी भी क्षेत्रीय समूह का सदस्य नहीं है।
हर साल एक अलग समूह का एक अलग देश G20 की अध्यक्षता संभालता है। हालाँकि, ब्लॉक के देशों को राष्ट्रपति पद पर बैठने का समान अधिकार है जब उनके ब्लॉक की बारी आती है। समूह 2 भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की वर्तमान अध्यक्षता है।
G20 प्रेसीडेंसी अन्य सदस्यों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास के जवाब में G20 एजेंडा को एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार है। निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, प्रेसीडेंसी को वर्तमान, तत्काल अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी "ट्रोइका" द्वारा समर्थित किया जाता है।
भारत की अध्यक्षता के दौरान, G20 ट्रोइका के सदस्य इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील हैं।

G20 की स्थापना
G20 की स्थापना 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में की गई थी।

नेताओं के स्तर तक उन्नति

2007 और 2009 के वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट के मद्देनजर, जब यह स्पष्ट हो गया कि आवश्यक संकट समन्वय केवल उच्चतम राजनीतिक स्तर पर ही संभव होगा, तो राज्य/सरकार के प्रमुखों के स्तर पर जी20 में सुधार किया गया। तब से, G20 नेता नियमित रूप से मिलते रहे हैं और G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच बन गया है।
G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक चक्राकार राष्ट्रपति के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। फोरम ने शुरू में बड़े पैमाने पर व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन बाद में व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी सहित अन्य को शामिल करने के लिए अपने एजेंडे का विस्तार किया है। अब तक आयोजित जी20 शिखर सम्मेलनों की सूची, उनके मुख्य फोकस क्षेत्रों के साथ, अनुबंध- II में दी गई है।

मेज़बान देश और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन
सदस्य देशों के अलावा, यानी 19 देश (अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, और संयुक्त राज्य अमेरिका) और यूरोपीय संघ, प्रत्येक G20 प्रेसीडेंसी अन्य अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (IOs) को G20 बैठकों और शिखर सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।
भारत ने G20 की अध्यक्षता के लिए बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है। अतिथि आईओ के लिए, भारत ने आईएसए, सीडीआरआई और एडीबी को नियमित जी20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (यूएन, आईएमएफ, डब्ल्यूबी, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ, एफएसबी और ओईसीडी) और क्षेत्रीय संगठनों (एयू, एयूडीए-नेपैड और आसियान) के अध्यक्षों को आमंत्रित किया है।).

“भारत की G20 प्रेसीडेंसी एकता की इस सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। इसलिए हमारा विषय है - 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य''' - प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी

1 दिसंबर, 2022 एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि भारत ने इंडोनेशिया से पदभार ग्रहण करते हुए जी20 फोरम की अध्यक्षता संभाली है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत की G20 अध्यक्षता पिछले 17 राष्ट्रपतियों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

जी20 की अध्यक्षता लेने के साथ ही, भारत LiFE आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अमृत काल पहल के माध्यम से सभी के लिए एक साझा वैश्विक भविष्य लाने के मिशन पर है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं और जीवन जीने के एक स्थायी तरीके को बढ़ावा देना है। एक स्पष्ट योजना और विकासोन्मुख दृष्टिकोण के साथ, भारत का लक्ष्य सभी के लिए नियम-आधारित व्यवस्था, शांति और न्यायपूर्ण विकास को बढ़ावा देना है। 2023 शिखर सम्मेलन से पहले नियोजित 200 से अधिक कार्यक्रम भारत के एजेंडे और भारत की जी20 अध्यक्षता की छह विषयगत प्राथमिकताओं को मजबूत करेंगे।

19 देशों और यूरोपीय संघ के G20 समूह की स्थापना 1999 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। कुल मिलाकर, G20 देश वैश्विक आबादी का लगभग दो-तिहाई, वैश्विक व्यापार का 75% और विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 85% हिस्सा हैं। 2007 के वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट के मद्देनजर, G20 को राज्य/सरकार के प्रमुखों के स्तर तक ऊपर उठाया गया और इसे "अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच" का नाम दिया गया।

G20 में सहभागिता के दो मुख्य ट्रैक हैं: वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। G20 की कार्यवाही का नेतृत्व शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जिन्हें सदस्य देशों के नेताओं के निजी दूत के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये शेरपा पूरे वर्ष होने वाली वार्ताओं की देखरेख करने, शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर विचार-विमर्श करने और के ठोस कार्यों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार हैं। जी20. दोनों ट्रैक में संबंधित पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ विशिष्ट विषयों को संबोधित करने के लिए कार्य समूह हैं।

इस वर्ष कार्य समूह हरित विकास, जलवायु वित्त, समावेशी विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी परिवर्तन और सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए महिला सशक्तिकरण के सुधार जैसे वैश्विक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये सभी कदम सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी लाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुरक्षित करने के लिए उठाए गए हैं।

भारत और जी-20

जी20 प्रक्रिया में भारत की भागीदारी एक प्रमुख के रूप में इस अहसास से उपजी है विकासशील अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता में भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है और वित्तीय प्रणाली. भारत शेरपाओं दोनों स्तरों पर जी20 की तैयारी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल रहा है अपनी स्थापना के बाद से ट्रैक और वित्तीय ट्रैक। सभी में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया सात G20 शिखर सम्मेलन. G20 शिखर सम्मेलन में भारत का एजेंडा लाने की आवश्यकता से प्रेरित है वित्तीय प्रणाली में अधिक समावेशिता, संरक्षणवादी प्रवृत्तियों से बचना और सबसे ऊपर यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकासशील देशों की विकास संभावनाएं प्रभावित न हों। भारत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि वैश्विक समुदाय का ध्यान आवश्यकता पर बना रहे उभरती अर्थव्यवस्थाओं को उनके विकास को पूरा करने के लिए वित्त का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करना जरूरत है. भारत ने जी20 प्रक्रिया के एजेंडा आइटम के रूप में विकास को शामिल करने का स्वागत किया है सियोल शिखर सम्मेलन और सियोल विकास आम सहमति का समर्थन किया संबद्ध बहु-वर्षीय कार्य योजनाएँ। प्रधान मंत्री ने अधिशेष के पुनर्चक्रण का आह्वान किया विकासशील देशों में निवेश में बचत न केवल तत्काल मांग को पूरा करने के लिए है असंतुलन लेकिन विकासात्मक असंतुलन भी। भारत ने G20 विचार-विमर्श की गतिशीलता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए काम किया है मजबूत, टिकाऊ और संतुलित विकास के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना, मजबूती प्रदान करना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नियामक प्रणालियाँ, ब्रेटन वुड्स के संस्थानों में सुधार, व्यापार वित्त को सुविधाजनक बनाना, दोहा एजेंडे को आगे बढ़ाना। भारत, के सह-अध्यक्ष के रूप में मजबूत, सतत और संतुलित विकास पर फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप ने प्रयास किया समूह की ऊर्जा को विकास, नौकरियों, राजकोषीय समेकन, पुनर्संतुलन की ओर पुनः केंद्रित करें सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की ओर मांग, और आंतरिक से उत्पन्न होने वाले जोखिम यूरोज़ोन के भीतर असंतुलन. भारत G20 प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है एक स्थिर, समावेशी और प्रतिनिधि वैश्विक आर्थिक और वित्तीय प्रणाली प्राप्त करना। रूस 1 दिसंबर 2012 से G20 की अध्यक्षता संभालेगा इसके बाद 2014 में ऑस्ट्रेलिया और 2015 में तुर्की का स्थान है। अगला G20 शिखर सम्मेलन निर्धारित है 2013 में रूस में आयोजित किया जाएगा।

भारत की G20 अध्यक्षता:

भारत 2023 में पहली बार G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन बुलाएगा, क्योंकि 43 प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख - G20 में अब तक का सबसे बड़ा - इस साल के अंत में सितंबर में अंतिम नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्र के रूप में, भारत का राष्ट्रपति बनना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा क्योंकि यह सभी के लाभ के लिए व्यावहारिक वैश्विक समाधान ढूंढना चाहता है और "वसुधैव कुटुंबकम" या "दुनिया एक परिवार है" के विचार को मूर्त रूप देना चाहता है।

G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक चक्रीय अध्यक्षता के साथ आयोजित किया जाता है, और 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता संभालेगा। समूह के पास कोई स्थायी सचिवालय नहीं है और इसे राष्ट्रपति पद के पिछले, वर्तमान और भविष्य के धारकों द्वारा समर्थित किया जाता है, जिन्हें ट्रोइका के रूप में जाना जाता है। 2023 में, ट्रोइका में इंडोनेशिया, ब्राजील और भारत शामिल हैं।

यह शिखर सम्मेलन दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक बैठकों के लिए संभावित मेजबान शहरों के साथ बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, इंदौर, जोधपुर, खजुराहो, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, कच्छ के रण सहित पूरे वर्ष बैठकों की एक श्रृंखला का समापन करेगा। , सूरत, तिरुवनंतपुरम, और उदयपुर।

वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अनुवाद "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" है, भारत की G20 अध्यक्षता का विषय है। यह एक पुराने संस्कृत ग्रंथ महा उपनिषद से प्रेरित है। विषय मूल रूप से सभी जीवन - मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्मजीव - के महत्व के साथ-साथ पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड पर उनकी परस्पर निर्भरता पर प्रकाश डालता है। यह विषय LiFE (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) का भी उदाहरण देता है, जो स्वच्छ, हरित और नीले भविष्य के निर्माण में व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जिम्मेदार जीवन शैली विकल्पों के महत्व पर प्रकाश डालता है।

जी20 की अध्यक्षता भारत के लिए "अमृतकाल" की शुरुआत की भी शुरुआत करती है, जो 15 अगस्त, 2022 को अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होने वाली 25 साल की अवधि है, जो इसकी स्वतंत्रता की शताब्दी तक ले जाएगी।

भारत की G20 प्राथमिकताएँ:

1. हरित विकास, जलवायु वित्त और जीवन

भारत का ध्यान जलवायु परिवर्तन पर है, जिसमें जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया गया है, साथ ही विकासशील देशों के लिए उचित ऊर्जा परिवर्तन सुनिश्चित किया गया है।
LiFE आंदोलन का परिचय, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं को बढ़ावा देता है और भारत की स्थायी परंपराओं पर आधारित है।

2. त्वरित, समावेशी और लचीला विकास

उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जिनमें संरचनात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता है, जिसमें वैश्विक व्यापार में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों का समर्थन करना, श्रम अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना, वैश्विक कौशल अंतर को संबोधित करना और समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणालियों का निर्माण करना शामिल है।
3. एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाना

सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता, जिसमें विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के प्रभाव को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
4. तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

प्रौद्योगिकी के प्रति मानव-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेशन और कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में तकनीक-सक्षम विकास जैसे क्षेत्रों में ज्ञान-साझाकरण बढ़ाना।
5. 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएँ

बहुपक्षवाद में सुधार लाने और एक अधिक जवाबदेह, समावेशी और प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाने का प्रयास जो 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त हो।
6. महिला नेतृत्व वाला विकास

सामाजिक-आर्थिक विकास और एसडीजी की उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए महिला सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व पर ध्यान देने के साथ समावेशी वृद्धि और विकास पर जोर दिया गया।

G20 संरचना
शेरपा ट्रैक
इसका नेतृत्व एक शेरपा करता है जो नेता का प्रतिनिधि होता है।

फोकस क्षेत्र: कृषि, भ्रष्टाचार विरोधी, जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार और निवेश जैसे सामाजिक-आर्थिक मुद्दे। इस ट्रैक के अंतर्गत कार्य समूहों में शामिल हैं:
I. कृषि कार्य समूह
द्वितीय. भ्रष्टाचार विरोधी टास्क फोर्स
तृतीय. संस्कृति कार्य समूह
चतुर्थ. विकास कार्य समूह
वी. डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप
VI. आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह
सातवीं. शिक्षा कार्य समूह
आठवीं. रोजगार कार्य समूह
नौवीं. ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह
X. पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह
XI. स्वास्थ्य कार्य समूह
बारहवीं. पर्यटन कार्य समूह
XIII. व्यापार और निवेश कार्य समूह
उपरोक्त कार्य समूहों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

वित्त ट्रैक

इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर करते हैं, जो आम तौर पर साल में चार बार मिलते हैं, जिसमें दो बैठकें डब्ल्यूबी/आईएमएफ बैठकों के साथ आयोजित की जाती हैं।
फोकस क्षेत्र: वैश्विक अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, वित्तीय विनियमन, वित्तीय समावेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना और अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे राजकोषीय और आर्थिक नीति मुद्दे। इस ट्रैक के अंतर्गत कार्य समूहों और वर्कफ़्लो में शामिल हैं:
I. फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप
द्वितीय. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह
तृतीय. इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप
चतुर्थ. सतत वित्त कार्य समूह
वी वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी
छठा. संयुक्त वित्त एवं स्वास्थ्य कार्य बल
सातवीं. अंतर्राष्ट्रीय कराधान मुद्दे
याद करना वित्तीय क्षेत्र में समस्याएँ
उपरोक्त कार्य समूहों और तंत्रों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। गतिविधि
• अनुसंधान और नवाचार गतिविधियों को समेकित करना
शेरपा ट्रैक वर्किंग ग्रुप के अलावा रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग (आरआईआईजी) का लक्ष्य जी20 सदस्य देशों के बीच अनुसंधान और नवाचार सहयोग को विस्तारित, तीव्र और मजबूत करना है। आरआईआईजी 2021 में इतालवी प्रेसीडेंसी के दौरान आयोजित शिक्षा फोरम का काम जारी रखता है, जिसमें जी20 सदस्य देशों के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार विशेषज्ञों को एक साथ लाया जाता है।

गतिविधि
अनुसंधान और नवाचार गतिविधियों को समेकित करें
शेरपा ट्रैक वर्किंग ग्रुप के अलावा रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग (आरआईआईजी) का लक्ष्य जी20 सदस्य देशों के बीच अनुसंधान और नवाचार सहयोग को विस्तारित, तीव्र और मजबूत करना है। आरआईआईजी 2021 में इतालवी प्रेसीडेंसी

के दौरान आयोजित शिक्षा फोरम का काम जारी रखता है, जिसमें जी20 सदस्य देशों के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार विशेषज्ञों को एक साथ लाया जाता है।

G20 को सशक्त बनाना
महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तिकरण और उन्नति के लिए G20 गठबंधन (G20 EMPOWER) 2019 में G20 ओसाका शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य व्यापारिक नेताओं और सरकार के बीच एक अद्वितीय गठबंधन का लाभ उठाकर निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना है। जी20 देश.
• अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन/अंतरिक्ष विभाग (ISRO/DOS) वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में अंतरिक्ष के महत्व पर चर्चा जारी रखने के लिए स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग (SELM) के चौथे संस्करण का आयोजन कर रहा है। SELM के पिछले संस्करण सऊदी अंतरिक्ष आयोग (2020), इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी (2021) और राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार एजेंसी, इंडोनेशिया (2022) द्वारा आयोजित किए गए थे। वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में नए स्थान के महत्व को पहचानते हुए, इस वर्ष की SELM थीम "टुवार्ड्स ए न्यू स्पेस एरा (अर्थव्यवस्था, जिम्मेदारी, गठबंधन)" है।

• G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार गोलमेज सम्मेलन (CSAR)
G20-CSAR भारत की वर्तमान G20 अध्यक्षता के दौरान शुरू की गई एक नई पहल है। G20-CSAR वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्रभावी संस्थागत व्यवस्था/मंच बनाने के उद्देश्य से G20 राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों को एक साथ लाएगा, जो तब एक प्रभावी और सुसंगत बन सकता है। एक। वैश्विक विज्ञान सलाहकार तंत्र। इसके अलावा, G20-CSAR का लक्ष्य वैश्विक S&T पारिस्थितिकी तंत्र के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों का समाधान करना है। भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान सीएसएआर के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में "वन हेल्थ" और वैश्विक भलाई के लिए साझा वैज्ञानिक बुनियादी ढांचा, और उभरती और भविष्य की प्रौद्योगिकियों और विकसित मानकों में सहयोग शामिल है। G20 CSAR की पहली बैठक 28 से 30 मार्च 2023 को उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के रामनगर में आयोजित की गई थी।

सहभागिता समूह
प्रासंगिक हितधारक समुदायों के साथ परामर्श करने की जी20 सदस्यों की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, जी20 सदस्यों में से प्रत्येक के गैर-सरकारी प्रतिभागियों को शामिल करने वाले सगाई समूहों के माध्यम से संवाद की सुविधा प्रदान की जाती है। ये समूह अक्सर G20 नेताओं के लिए सिफारिशें तैयार करते हैं जो नीति-निर्माण प्रक्रिया में योगदान करते हैं। सहभागिता समूह इस प्रकार हैं:
I. व्यवसाय20
द्वितीय. सिविल 20
तृतीय. श्रमिक 20
चतुर्थ. संसद20
वी. विज्ञान20
VI SAI20
सातवीं. स्टार्टअप20
आठवीं. 20 सोचो
नौवीं. शहरी20
एक्स. महिला20
XI. युवा 20

उपरोक्त सहभागिता समूहों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। भारत की G20 प्रेसीडेंसी 2023

भारत की G20 अध्यक्षता पर नवीनतम जानकारी और नियमित अपडेट के लिए, जिसमें प्रेस विज्ञप्तियाँ, दस्तावेज़, भाषण, फोटो गैलरी और G20 बैठकों के वीडियो शामिल हैं, कृपया देखें:
https://www.g20.org.
इसके अतिरिक्त, लाइव अपडेट को G20 इंडिया (@g20org)/ट्विटर पर एक्सेस किया जा सकता है; www.facebook.com/g20org; www.instagram.com/g20org; और www.youtube.com/@g20orgindia.

अनुबंध
शेरपा ट्रैक कार्य समूह
I. कृषि कार्य समूह
अनुबंध- मैं
वैश्विक खाद्य कीमतों की अस्थिरता को संबोधित करने के लिए 2011 में फ्रांसीसी प्रेसीडेंसी के दौरान G20 कृषि प्रतिनिधि समूह बनाया गया था। तब से यह कृषि-संबंधित मुद्दों पर जी20 सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जो संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा, विशेष रूप से शून्य भूख (एसडीजी 2) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। कार्य समूह खाद्य सुरक्षा, पोषण, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, खाद्य अपशिष्ट और हानि, स्थिरता और लचीले और समावेशी खाद्य मूल्य श्रृंखला जैसे वैश्विक मुद्दों पर जानकारी साझा करने और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।
द्वितीय. भ्रष्टाचार विरोधी टास्क फोर्स
भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह (ACWG) की स्थापना 2010 में की गई थी। भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर जी20 नेताओं को रिपोर्ट करता है और इसका लक्ष्य भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जी20 देशों की कानूनी प्रणालियों में कम से कम सामान्य मानक स्थापित करना है। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की अखंडता और पारदर्शिता, रिश्वत-विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संपत्ति की वसूली, लाभकारी स्वामित्व पारदर्शिता, कमजोर क्षेत्रों और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।
तृतीय. संस्कृति कार्य समूह
G20 संस्कृति मंत्री 2020 में पहली बार मिले और G20 एजेंडा को आगे बढ़ाने में संस्कृति के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। संस्कृति और अन्य नीति क्षेत्रों के बीच तालमेल को पहचानते हुए, और विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों पर संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के प्रभाव को पहचानते हुए, संस्कृति को सांस्कृतिक कार्य समूह (सीडब्ल्यूजी) के रूप में जी20 एजेंडे में एकीकृत किया गया था। 2021. समूह का लक्ष्य सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहयोग को मजबूत करना है।

चतुर्थ. विकास कार्य समूह
डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप (DWG) ने 2010 में अपनी स्थापना के बाद से G20 'विकास एजेंडा' के संरक्षक के रूप में कार्य किया है। 2015 में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और उसके लक्ष्यों को अपनाने के बाद, डीडब्ल्यूजी ने शेरपाओं की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी20 सतत विकास एजेंडा को आगे बढ़ाना और 2030 एजेंडा को प्राप्त करने के प्रयासों के साथ जी20 कार्यों के सतत विकास प्रतिच्छेदन को बेहतर ढंग से समझने के लिए अन्य कार्य धाराओं के साथ काम करना।

वी. डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप
2021 में स्थापित डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (DEWG) नीति निर्माताओं को अर्थव्यवस्थाओं की डिजिटल क्षमता का दोहन करने के लिए प्रेरणा और व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है। टास्क फोर्स का लक्ष्य सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने और समावेशी सामाजिक और आर्थिक विकास को साकार करने के लिए डिजिटल परिवर्तन करना है।

VI. आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह
आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर कार्य समूह (DRRWG) इंडोनेशियाई प्रेसीडेंसी सहित पिछले G20 अध्यक्षों के बीच आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर हुई पिछली चर्चाओं पर आधारित होगा, और आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों के लिए नए सिरे से तात्कालिकता की भावना प्रदान करेगा। यह जलवायु स्थिरता, बुनियादी ढांचे और विकास कार्य समूहों सहित अन्य G20 कार्य समूहों के साथ भी काम करेगा। G20 देशों के पास कई संस्थानों और विषयों में तकनीकी उपकरण हैं जिन्हें G20 देशों के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर 2030 तक आपदा नुकसान को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर लाया जा सकता है।

सातवीं. शिक्षा कार्य समूह
एजुकेशन वर्किंग ग्रुप (EdWG) की स्थापना 2018 में अर्जेंटीना की अध्यक्षता के दौरान की गई थी। EdWG सीखने के परिणामों को मजबूत करने और तकनीकी उपकरणों, डिजिटलीकरण, सार्वभौमिक गुणवत्ता वाली शिक्षा, वित्तपोषण, साझेदारी और शिक्षा तक समान पहुंच पर ध्यान केंद्रित करता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग। एडडब्ल्यूजी कौशल विकास और स्कूल-टू-वर्क संक्रमण जैसे क्रॉस-कटिंग मुद्दों को संबोधित करने के लिए रोजगार और अन्य डब्ल्यूजी के साथ सहयोग करता है।

आठवीं. रोजगार कार्य समूह
रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) रोजगार पर जी20 टास्क फोर्स के रूप में शुरू हुआ - 2011 में फ्रांसीसी प्रेसीडेंसी के तहत स्थापित - जिसे ऑस्ट्रेलियाई प्रेसीडेंसी के तहत नेताओं की घोषणा के बाद 2014 में कार्य समूह स्तर तक बढ़ा दिया गया था। EWG की पहली बैठक किसके तहत आयोजित की गई थी? 2015 में तुर्की के राष्ट्रपति पद. ईडब्ल्यूजी मजबूत, टिकाऊ, संतुलित, समावेशी और नौकरी-समृद्ध विकास के लिए श्रम, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करता है।

नौवीं. ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह
2009 से जी20 में टिकाऊ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में ऊर्जा पर चर्चा की गई है। ऊर्जा संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए 2013 में एक समर्पित ऊर्जा स्थिरता कार्य समूह की स्थापना की गई थी। 2017 में, जलवायु स्थिरता कार्य समूह के हिस्से के रूप में ऊर्जा पर चर्चा की गई थी। 2018 में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति पद के दौरान, ऊर्जा मुद्दों को जलवायु से अलग कर दिया गया और ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह (ईटीडब्ल्यूजी) के भीतर ऊर्जा संक्रमण पर चर्चा हुई। कार्य समूह ऊर्जा सुरक्षा, पहुंच और सामर्थ्य, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, नवाचार, प्रौद्योगिकी और वित्तपोषण पर चर्चा करता है।

X. पर्यावरण प्रतिनिधियों की बैठक और जलवायु स्थिरता कार्य समूह
जलवायु स्थिरता कार्य समूह (सीएसडब्ल्यूजी) की स्थापना 2018 में अर्जेंटीना की अध्यक्षता में की गई थी, जबकि पर्यावरण प्रतिनिधियों की बैठक (ईडीएम) जापान की अध्यक्षता में 2019 में शुरू हुई थी। ईडीएम और सीएसडब्ल्यूजी पर्यावरण और जलवायु मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनमें संसाधन दक्षता, परिपत्र अर्थव्यवस्था, महासागर स्वास्थ्य, समुद्री कूड़ा, मूंगा चट्टानें, भूमि क्षरण, जैव विविधता हानि, जल संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन को कम करने और अनुकूलित करने के तरीके शामिल हैं।
XI. स्वास्थ्य कार्य समूह
प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर संवाद बढ़ाने और G20 नेताओं को सूचित करने के लिए 2017 में जर्मन प्रेसीडेंसी के तहत एक स्वास्थ्य कार्य समूह (HWG) की स्थापना की गई थी। समूह वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए समान स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध एक स्थायी कल्याण समाज बनाने की दिशा में काम करता है। स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी, एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण, डिजिटल स्वास्थ्य, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन, टिकाऊ वित्तपोषण आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है।
बारहवीं. पर्यटन कार्य समूह
2020 में अपनी स्थापना के बाद से, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप (TWG) ने स्थानीय और वैश्विक पर्यटन को और विकसित करने के साथ-साथ इस क्षेत्र के सामने आने वाली आम चुनौतियों को कम करने के लिए चर्चा, विचार-विमर्श और कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन करने के लिए सदस्य देशों और संबंधित हितधारकों को एक साथ लाया है। COVID-19 महामारी के साथ। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका और इसकी प्रगति को देखते हुए, एजेंडा 2030 को प्राप्त करने के लिए, पर्यटन को अधिक टिकाऊ बनाना और इसकी लचीलापन बढ़ाना हाल के वर्षों में कार्य समूह का मुख्य फोकस रहा है।

XIII. व्यापार और निवेश कार्य समूह
व्यापार और निवेश कार्य समूह (TIWG) की स्थापना 2016 में की गई थी। यह G20 व्यापार और निवेश तंत्र को मजबूत करने, वैश्विक व्यापार विकास को बढ़ावा देने, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन करने, वैश्विक निवेश नीति सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने और समावेशिता और समन्वय को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएँ।

वित्त कार्य समूहों और वर्कफ़्लो को ट्रैक करता है

I. फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (एफडब्ल्यूजी) वर्तमान प्रासंगिकता के वैश्विक व्यापक आर्थिक मुद्दों, वैश्विक जोखिमों और अनिश्चितताओं की निगरानी और जी20 में मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास (एसएसबीआईजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति समन्वय के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करता है। भारत और ब्रिटेन कार्य समूह के सह-अध्यक्ष हैं।
द्वितीय. इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर (आईएफए) वर्किंग ग्रुप वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट (जीएफएसएन) जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय आर्किटेक्चर से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है; विकास वित्त से संबंधित मामले; क्रेडिट भेद्यता का प्रबंधन करना और क्रेडिट पारदर्शिता बढ़ाना; पूंजी प्रवाह का प्रबंधन करना और स्थानीय मुद्रा बांड बाजारों को बढ़ावा देना। कार्य समूह की अध्यक्षता कोरिया गणराज्य और फ्रांस द्वारा की जाती है।
तृतीय. इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप (IWG) इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करता है जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर को परिसंपत्ति वर्ग के रूप में विकसित करना शामिल है; गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निवेश को बढ़ावा देना; इन्फ्राटेक; और बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए नवीन उपकरणों की पहचान करना। कार्य समूह की सह-अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील द्वारा की जाती है।
चतुर्थ. सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप (SFWG) 2021 G20 इटालियन प्रेसीडेंसी के तहत अमेरिका और चीन की सह-अध्यक्षता वाला एक नव स्थापित समूह है। कार्य समूह इस बात पर चर्चा करता है कि जी20, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य हितधारकों को सतत वित्त एजेंडा की प्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने में कैसे मदद की जाए और उठाए जाने वाले प्रमुख कार्यों पर आम सहमति बनाई जाए।
वी. वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी (जीपीएफआई) वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। कुछ कार्य क्षेत्रों में वित्तीय प्रणाली के बुनियादी ढांचे में सुधार के तरीके, उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए अनुकूल नीतियों को लागू करना, प्रेषण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना और प्रेषण हस्तांतरण की लागत को कम करना, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता और डिजिटल विभाजन को पाटना शामिल है। दूसरों के बीच में। जीपीएफआई की सह-अध्यक्षता इटली और रूस द्वारा की जाती है।

संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्य बल (JFHTF) की स्थापना G20 रोम लीडर्स समिट, 2021 के दौरान की गई थी। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया (पीपीआर) पर संवाद और वैश्विक सहयोग और आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। अनुभव और सर्वोत्तम अभ्यास, वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच समन्वय तंत्र विकसित करना, सीमा पार निहितार्थों के साथ स्वास्थ्य आपात स्थितियों के सामूहिक कार्रवाई, मूल्यांकन और समाधान को बढ़ावा देना और एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को अपनाते हुए महामारी के पीपीआर के लिए संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को बढ़ावा देना।

सातवीं. G20 फाइनेंस ट्रैक में अंतर्राष्ट्रीय कराधान एजेंडा पर सीधे G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्टी के स्तर पर चर्चा की जाती है, और G20 के तत्वावधान में कराधान पर कोई औपचारिक कार्य समूह नहीं है। समूह के तहत जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियों का समाधान करना, कर चोरी से लड़ना, बैंक गोपनीयता और टैक्स हेवन को समाप्त करना, सूचना साझा करना और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर चोरी शामिल है। G20 अंतर्राष्ट्रीय कर एजेंडे पर काम OECD के व्यापक ढांचे के भीतर किया जाता है।
याद करना वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों से संबंधित चर्चाएँ सीधे G20 वित्त और सेंट्रल बैंक डिप्टी के स्तर पर होती हैं और कोई औपचारिक कार्य समूह नहीं है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड G20 आर्थिक क्षेत्र के एजेंडे पर प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा की सुविधा के लिए आवश्यक चर्चा पत्र प्रदान करता है। चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को मजबूत करना, विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण, जोखिम प्रबंधन में सुधार, पर्यवेक्षी कॉलेजों की स्थापना, सीमा पार भुगतान में वृद्धि, गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों (एनबीएफआई) में संरचनात्मक कमजोरियों को संबोधित करना और जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिम शामिल हैं। का मूल्यांकन सम्मिलित है। दूसरों के बीच क्रिप्टो परिसंपत्तियां और नीतिगत जोखिम।
सहभागिता समूह
I. व्यवसाय20

Business20 (B20), आधिकारिक तौर पर 2010 में लॉन्च किया गया, वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 संवाद मंच है। यह आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक आवर्ती राष्ट्रपति द्वारा स्थापित प्राथमिकताओं पर ठोस कार्रवाई योग्य नीति सिफारिशें प्रदान करता है। यह सर्वसम्मति-आधारित नीति प्रस्तावों को विकसित करने के लिए G20 और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थानों को सौंपे गए कार्य बलों और कार्रवाई सम्मेलनों के माध्यम से काम करता है।

द्वितीय. सिविल 20
सिविल20 (सी20) एंगेजमेंट ग्रुप को 2013 में आधिकारिक जी20 एंगेजमेंट ग्रुप के रूप में लॉन्च किया गया था, हालांकि जी20 सदस्य देशों के बीच नागरिक समाज की भागीदारी 2010 में शुरू हुई थी। C20 दुनिया भर के सिविल सोसाइटी संगठनों (CSO) के लिए एक मंच प्रदान करता है। G20 के लिए सरकारी और गैर-व्यावसायिक आवाज़ें। यह एक स्थान प्रदान करता है जिसके माध्यम से वैश्विक सीएसओ संरचित और टिकाऊ तरीके से जी20 में योगदान कर सकते हैं।

तृतीय. श्रमिक 20
Labour20 (L20) शिखर सम्मेलन पहली बार औपचारिक रूप से 2011 में फ्रांसीसी प्रेसीडेंसी के दौरान आयोजित किया गया था। L20 G20 देशों के ट्रेड यूनियन नेताओं को बुलाता है और श्रम-संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से विश्लेषण और नीति सिफारिशें प्रदान करता है।

चतुर्थ. संसद20
पार्लियामेंट20 (पी20) एंगेजमेंट ग्रुप, जिसे 2010 में कनाडा की अध्यक्षता में लॉन्च किया गया था, का नेतृत्व जी20 देशों की संसदों के वक्ताओं द्वारा किया जाता है। चूँकि सांसद संबंधित सरकारों को मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, P20 बैठकों का उद्देश्य वैश्विक शासन में संसदीय आयाम लाना, जागरूकता बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के लिए राजनीतिक समर्थन बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें प्रभावी ढंग से राष्ट्रीय वास्तविकताओं में अनुवादित किया जाए।

वी. विज्ञान20
G20 देशों की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों को शामिल करने वाला साइंस20 (S20) एंगेजमेंट ग्रुप 2017 में जर्मनी की अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया था। यह नीति निर्माताओं को अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों से युक्त एक टास्क फोर्स द्वारा तैयार की गई सर्वसम्मति-आधारित विज्ञान-आधारित सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
VI. SAI20
सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 (SAI20) 2022 में इंडोनेशियाई प्रेसीडेंसी द्वारा शुरू किया गया एक जुड़ाव समूह है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और G20 सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर SAI द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करने का एक मंच है।

सातवीं. स्टार्टअप20
स्टार्टअप आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। वे सहयोग बढ़ाने और सीमाओं के पार नवाचार को बढ़ावा देने और एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्थाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए मंच और उपकरण प्रदान करते हैं। प्रस्तावित स्टार्टअप20 सहभागिता समूह का लक्ष्य विकास चुनौतियों और अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए जी20 नेताओं को कार्रवाई की सिफारिश करना है।

आठवीं. 20 सोचो
थिंक20 (टी20), आधिकारिक जी20 सहभागिता समूह के रूप में, 2012 में मैक्सिकन प्रेसीडेंसी के दौरान लॉन्च किया गया था। यह G20 के लिए एक "विचार बैंक" के रूप में कार्य करता है, जो प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थिंक टैंक और उच्च-स्तरीय विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। . T20 अनुशंसाओं को नीति संक्षेप में संश्लेषित

किया जाता है और G20 कार्य समूहों, मंत्रिस्तरीय बैठकों और नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है ताकि G20 को ठोस नीतिगत उपाय करने में मदद मिल सके।

नौवीं. शहरी20
अर्बन20 (U20) की स्थापना दिसंबर 2017 में अर्जेंटीना की अध्यक्षता में पेरिस में वन प्लैनेट समिट में की गई थी। यह शहर के नेताओं के लिए शहरीकरण के मुद्दों, एसडीजी लक्ष्यों और शहरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर संयुक्त रूप से चर्चा करने के लिए एक औपचारिक सहभागिता समूह है।

एक्स. महिला20
Women20 (W20) एक सगाई समूह है जिसे 2015 में तुर्की राष्ट्रपति पद के दौरान लॉन्च किया गया था। W20 का प्राथमिक उद्देश्य 2014 में ब्रिस्बेन शिखर सम्मेलन में अपनाई गई "25x25" प्रतिबद्धता को लागू करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक श्रम बल भागीदारी में लिंग अंतर को 25% तक कम करना है। W20 'लिंग समावेशी आर्थिक विकास' पर केंद्रित है, और निम्नलिखित तीन स्तंभ इसके समर्थन के मुख्य क्षेत्र हैं: श्रम समावेशन, वित्तीय समावेशन और डिजिटल समावेशन।

XI. युवा 20
यूथ20 (वाई20), 2010 में आयोजित पहले वाई20 सम्मेलन के साथ, एक मंच प्रदान करता है जो युवाओं को जी20 प्राथमिकताओं के बारे में अपने दृष्टिकोण और विचारों को व्यक्त करने और जी20 नेताओं को प्रस्तुत की गई सिफारिशों की एक श्रृंखला के साथ आने की अनुमति देता है।

पिछला G20 शिखर सम्मेलन

वाशिंगटन डीसी, लंदन, पिट्सबर्ग - 2008 और 2009
पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन डीसी (यूएसए) में आयोजित किया गया था। इसने 60 से अधिक वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था में सबसे नाटकीय सुधारों में से एक के लिए परिदृश्य तैयार किया। 2009 में लंदन (यूके) में एक अनुवर्ती शिखर सम्मेलन में, जी20 उन राज्यों को ब्लैकलिस्ट करने पर सहमत हुआ जो कर चोरी और कर चोरी के प्रयासों में सहयोग करने से इनकार करते हैं। 2008 के वित्तीय संकट के मद्देनजर, जी20 ने हेज फंड और रेटिंग एजेंसियों पर सख्त नियंत्रण लगाने का फैसला किया। संस्थागत सुधारों में वित्तीय स्थिरता फोरम (एफएसएफ) का विस्तार शामिल है ताकि इसे वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए एक प्रभावी पर्यवेक्षक और निगरानी निकाय बनाया जा सके। इसका नाम बदलकर वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) कर दिया गया। 2008 के वित्तीय संकट के बाद संरक्षणवाद की ओर बदलाव को उलटने में मदद करने का श्रेय G20 को दिया जाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बजट को तीन गुना करने और बहुपक्षीय विकास बैंकों के अधिदेश और ऋण देने का विस्तार करने के लिए आम सहमति बनाने में भी मदद मिली। 2008 में, वाशिंगटन डीसी में, G20 ने 12 महीनों के लिए व्यापार और निवेश पर नई बाधाएँ लगाने से परहेज करने पर सहमति व्यक्त की। इनमें से प्रत्येक बाद के शिखर सम्मेलन में प्रावधान बढ़ाया गया है। 2009 में पिट्सबर्ग (यूएसए) में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन ने G20 को वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित मामलों पर मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया। शिखर सम्मेलन ने बैंकिंग क्षेत्र के लिए सख्त नियमों पर निर्णय लिया, जिससे बैंकों को पूंजी निर्माण के लिए अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा बनाए रखने की आवश्यकता होगी। इन उपायों से सरकार और उच्च जोखिम वाली निजी क्षेत्र की गतिविधियों के करदाताओं को वित्तीय जोखिम कम करने में मदद मिली।
टोरंटो, सियोल, कान्स - 2010 और 2011
2010 में टोरंटो शिखर सम्मेलन (कनाडा) में, G20 ने संप्रभु ऋण को कम करने के निर्देशों को अपनाया। उन्नत औद्योगिकीकृत राज्यों ने अपने बजट घाटे और विदेशी ऋण को कम करने का वचन दिया। जी20 नेताओं की 2010 में सियोल (कोरिया गणराज्य) में फिर से मुलाकात हुई, जहां उन्होंने बैंकों के लिए सख्त नियम (बेसल III मानदंड) अपनाए, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में आर्थिक साझेदारी और वोटिंग शेयरों में सुधार पर सहमति व्यक्त की। जी20 के इतिहास में सियोल एक मील का पत्थर था। पहली बार, विकास नीति के मुद्दे 'सियोल आम सहमति' के नाम से जाने जाने वाले शिखर सम्मेलन के एजेंडे में थे। प्रत्येक आगामी शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा का विकास एक मानक हिस्सा रहा है। 2011 में कान्स (फ्रांस) में

आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के कार्य कार्यक्रम का केंद्र बिंदु अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का सुधार था। जी20 नेता एक कृषि बाजार सूचना प्रणाली, खाद्य बाजारों में पारदर्शिता बढ़ाने और संकट के समय में अंतरराष्ट्रीय नीति समन्वय को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर-एजेंसी मंच स्थापित करने पर भी सहमत हुए।

लॉस काबोस, सेंट पीटर्सबर्ग, ब्रिस्बेन - 2012, 2013 और 2014
लॉस काबोस (मेक्सिको) में 2012 का शिखर सम्मेलन युवा बेरोजगारी से निपटने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज और सभ्य आय के साथ गुणवत्तापूर्ण नौकरियां पैदा करने पर केंद्रित था। शिखर सम्मेलन ने विकास एजेंडा, कृषि और हरित विकास के बीच संबंध पर भी प्रकाश डाला। 2013 में सेंट पीटर्सबर्ग (रूस) में कर चोरी और कर चोरी से निपटने में बड़ी प्रगति हुई थी। जी20 कर सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान और आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) पर एक कार्य योजना पर सहमत हुआ। इसका उद्देश्य कर चोरी में लगे बहुराष्ट्रीय व्यवसायों की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए एक नियामक रणनीति तैयार करने में मदद करना था, जिससे लाभ कम हो सके और लाभ को उन स्थानों से दूर स्थानांतरित किया जा सके जहां लाभ कमाने वाली गतिविधियां की जाती हैं। 2014 में ब्रिस्बेन शिखर सम्मेलन (ऑस्ट्रेलिया) में, जी20 ने अपनी सामूहिक जीडीपी को दो प्रतिशत बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। बैंकिंग विनियमन के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जिसमें वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर ने कर सूचनाओं के स्वचालित आदान-प्रदान के लिए सामान्य रिपोर्टिंग मानकों को मंजूरी दी। नेताओं ने 'ब्रिस्बेन 25 बाय 25' लक्ष्य का समर्थन किया, जिसका लक्ष्य 2025 तक कार्यबल को 25 प्रतिशत तक कम करना है।

अंताल्या और हांग्जो - 2015 और 2016
2015 में अंताल्या (तुर्की) में G20 शिखर सम्मेलन में, G20 ने पहली बार प्रवासन और शरणार्थी आंदोलनों पर ध्यान दिया। वे आगे के आर्थिक सुधारों पर भी सहमत हुए और वैश्विक जलवायु समझौते का समर्थन करने का वादा किया। नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर जी-20 का बयान भी जारी किया। हांग्जो (चीन) में 2016 के शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक समावेशी विकास पर जोर दिया गया था। शिखर सम्मेलन में सतत विकास और सामाजिक कल्याण को जोड़ने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। डिजिटल अर्थव्यवस्था 2016 में चीन की अध्यक्षता के दौरान विकास और प्रगति के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में पहली बार जी20 एजेंडे का हिस्सा बन गई। G20 नेताओं ने 'सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा पर G20 कार्य योजना' को भी अपनाया, जो तब से एक मार्गदर्शक बन गया है। 'सतत विकास' पर G20 के कार्य के लिए दस्तावेज़।

हैम्बर्ग - 2017
जर्मन प्रेसीडेंसी के तहत G20 बैठक "एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड" थीम के तहत आयोजित की गई थी, जिसमें आतंकवाद के वैश्विक खतरे को संबोधित करने पर विशेष जोर दिया गया था। शिखर सम्मेलन की कार्यवाही की औपचारिक शुरुआत से पहले 'आतंकवाद से लड़ना' विषय पर जी20 लीडर्स रिट्रीट का आयोजन किया गया था। 2017 शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा अपनाई गई हैम्बर्ग घोषणा ने पेरिस समझौते की "अपरिवर्तनीयता" को मान्यता दी। इसने ऊर्जा प्रणाली परिवर्तन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में ऊर्जा सुरक्षा पर प्रकाश डाला और बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) से सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देने का आह्वान किया। जी20 नेताओं ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और विकास के लिए वित्तपोषण पर अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा के साथ अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। शिखर सम्मेलन में G20 अफ्रीका साझेदारी को 'G20 कॉम्पैक्ट विद अफ्रीका' के नाम से भी जाना जाता है।
ब्यूनस आयर्स - 2018
अर्जेंटीना की अध्यक्षता में जी20 का मुख्य विषय 'सतत विकास के लिए आम सहमति बनाना' था। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति पद के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे - काम का भविष्य; चौथी औद्योगिक क्रांति, स्वास्थ्य, युवा, विकास के लिए बुनियादी ढांचा; और स्थायी खाद्य सुरक्षा। जी20 ने महिलाओं को सशक्त बनाने, भ्रष्टाचार से लड़ने, हमारे वित्तीय प्रशासन को मजबूत करने, एक मजबूत और टिकाऊ वित्तीय प्रणाली, वैश्विक कर प्रणाली की निष्पक्षता, व्यापार और निवेश, जलवायु कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर पिछले राष्ट्रपतियों की विरासत को आगे बढ़ाने की मांग की। दूसरों के बीच में। एक लचीली और स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली।

ओसाका - 2019

2019 में G20 शिखर सम्मेलन (जापान) व्यापार और निवेश जैसे प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित है; स्टील की अतिरिक्त क्षमता; डिजिटलीकरण; विश्वास के साथ डेटा मुक्त प्रवाह; आधार क्षरण और लाभ साझाकरण पर जी20/ओईसीडी ढांचा; गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचा निवेश; भ्रष्टाचार विरोधी; जलवायु परिवर्तन; ऊर्जा; पर्यावरण; विस्थापन एवं प्रवासन. जी20 नेताओं ने 'आतंकवाद के लिए इंटरनेट के शोषण और आतंकवाद के लिए हिंसक उग्रवाद (वीईसीटी) का मुकाबला' पर एक ऐतिहासिक बयान जारी किया।

सऊदी अरब - 2020

15वां G20 शिखर सम्मेलन 'सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को साकार करना' विषय के तहत आयोजित किया गया था। यह G20 के इतिहास में पहला आभासी शिखर सम्मेलन था। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर, सऊदी प्रेसीडेंसी ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करने और एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए 25 मार्च 2020 को एक 'असाधारण वर्चुअल जी20 लीडर्स' शिखर सम्मेलन भी बुलाया। इसके बाद नेताओं ने कोविड-19 पर एक बयान जारी किया और महामारी से लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की; वैश्विक अर्थव्यवस्था की रक्षा करना; अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को दूर करना और महामारी से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाना। जी20 ने महामारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई। सऊदी राष्ट्रपति पद के तहत, नेताओं ने ऋणग्रस्त देशों को तरलता राहत प्रदान करने के लिए ऋण सेवा निलंबन पहल और डीएसएसआई से परे ऋण उपचार के लिए एक सामान्य ढांचे को मंजूरी दी, ताकि वे अपने संसाधनों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। महामारी के नागरिक और आर्थिक प्रभाव को संबोधित करें। आज तक, डीएसएसआई ने 45 से अधिक देशों को 5 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है और इसे 2021 के अंत तक बढ़ा दिया गया है।

सऊदी राष्ट्रपति पद के महत्वपूर्ण परिणामों में COVID-19 के जवाब में एक कार्य योजना को अपनाना और वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की एक संयुक्त बैठक बुलाना, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली में सुधार पर चर्चा में महत्वपूर्ण प्रगति शामिल है। G20 ने सशक्तिकरण के लिए एक निजी क्षेत्र गठबंधन स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की और सऊदी राष्ट्रपति पद के दौरान महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व की प्रगति (EMPOWER) की शुरुआत की।

इटली - 2021

इटली ने 30-31 अक्टूबर 2021 को रोम में 16वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। G20 की अध्यक्षता के लिए इटली द्वारा चुनी गई थीम 'लोग, ग्रह, समृद्धि' चार व्यापक विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित है: (i) महामारी से उबरना और वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन; (ii) आर्थिक सुधार और लचीलापन; (iii) जलवायु परिवर्तन; और (iv) सतत विकास और खाद्य सुरक्षा। इतालवी अध्यक्षता के तहत जी20 कैलेंडर में प्रमुख आकर्षण विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन (ईयू के साथ साझेदारी में), विदेश और विकास मंत्रियों की पहली जी20 संयुक्त बैठक, खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित विकास मंत्रियों की एक अलग बैठक, जी20 की पहली बैठक हैं। अनुसंधान मंत्री, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन और वित्त मंत्रियों की संयुक्त बैठक।

मई 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में, G20 नेताओं ने रोम घोषणापत्र को अपनाया, जिसमें बेहतर रोकथाम, पता लगाने और प्रतिक्रिया देने और COVID-19 महामारी को समाप्त करने और पुनर्प्राप्ति का समर्थन करने के लिए मजबूत बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त प्रयासों में योगदान जारी रखने का आह्वान किया गया। वैश्विक स्वास्थ्य खतरे और आपात्कालीन परिस्थितियाँ। G20 ने कृषि क्षेत्र के परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करके खाद्य सुरक्षा, कुपोषण और भूख जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए 'खाद्य सुरक्षा और पोषण पर मटेरा घोषणा' पर हस्ताक्षर किए।

जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने कर चुनौतियों से निपटने के लिए दो-स्तंभीय समाधान पर एक अंतिम राजनीतिक समझौते को भी मंजूरी दे दी, जो एक सदी से भी अधिक समय में सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक कर सुधार है, जिसके तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम से कम 15% कर का भुगतान करना अनिवार्य होगा। उनके संचालन के देश।

इसके अलावा, इटली ने अफगानिस्तान पर एक असाधारण नेताओं का शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया, जो अफगानिस्तान पर विदेश मंत्रियों की एक बैठक से पहले आयोजित किया गया था, जिसमें अफगानिस्तान में संकट पर 20 की प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई, विशेष रूप से मानवीय पहुंच सुनिश्चित करना; सुरक्षा बनाए रखना और आतंकवाद तथा गतिशीलता और प्रवासन के मुद्दों से लड़ना। शिखर सम्मेलन के बाद एक राष्ट्रपति का बयान जारी किया गया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जी20 की

वकालत की भूमिका की बात की गई जो संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों का पूरी तरह से समर्थन करता है और मानवीय सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र की अपील का जवाब देता है, और तालिबान से आतंकवादी समूहों के साथ अपने संबंध तोड़ने का आह्वान किया।

इंडोनेशिया - 2022

इंडोनेशिया ने कोविड-19 महामारी से एक मजबूत और व्यापक वैश्विक पुनर्प्राप्ति को आगे बढ़ाने के तरीके के रूप में अपने राष्ट्रपति पद के लिए समग्र विषय के रूप में "टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर" को चुना। विचार दुनिया में सामूहिक पुनर्प्राप्ति की भावना को प्रतिबिंबित करना था और यह सुनिश्चित करना था कि जी20 सामूहिक पुनर्प्राप्ति में सहायता के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण पेश करे और हरित और समावेशी विकास के एक नए अध्याय की ओर बढ़े।

प्रेसीडेंसी ने तीन मुख्य स्तंभों की पहचान की: i) वैश्विक स्वास्थ्य वास्तुकला - भविष्य में किसी भी महामारी के लिए वैश्विक समुदाय की यात्रा और लचीलेपन के लिए वैश्विक स्वास्थ्य मानकों की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत वैश्विक सहयोग; ii) डिजिटल परिवर्तन - डिजिटल युग में समान समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के तेजी से डिजिटलीकरण से वास्तविक क्षमता का एहसास; और iii) सतत ऊर्जा परिवर्तन - वैश्विक समुदाय के लिए स्वच्छ और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन में तेजी लाने के लिए नए दृष्टिकोण और आयाम।

"एक साथ उबरें, मजबूत होकर उबरें" थीम को ध्यान में रखते हुए, G20 नेताओं ने घोषणा की:

• अपनी व्यापक आर्थिक नीति प्रतिक्रिया और सहयोग में चुस्त और लचीले रहें, सार्वजनिक निवेश और संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा दें, निजी निवेश को बढ़ावा दें और बहुपक्षीय व्यापार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को मजबूत करें, दीर्घकालिक विकास, टिकाऊ और समावेशी, हरित और न्यायपूर्ण संक्रमण, और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय बैंक मूल्य स्थिरता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

• व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता की रक्षा करें और वित्तीय लचीलेपन को मजबूत करने और स्थायी वित्त और पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए, नकारात्मक जोखिमों को कम करने के लिए सभी उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध रहें।

• खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और बाजार स्थिरता का समर्थन करने के लिए, मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए अस्थायी और लक्षित सहायता प्रदान करना, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच संचार को मजबूत करना और दीर्घकालिक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों, लचीले और टिकाऊ भोजन के लिए व्यापार और निवेश बढ़ाना , उर्वरक और ऊर्जा प्रणाली।

• विभिन्न प्रकार के नवीन वित्तपोषण स्रोतों और उपकरणों के माध्यम से, एसडीजी की उपलब्धि का समर्थन करने, निजी निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए निम्न और मध्यम आय और अन्य विकासशील देशों के लिए और अधिक निवेश को अनलॉक करना। बहुपक्षीय विकास बैंकों को एसडीजी हासिल करने और सतत विकास और बुनियादी ढांचे के निवेश सहित वैश्विक चुनौतियों का जवाब देने के लिए अपने अधिदेशों को जुटाने और अतिरिक्त वित्तपोषण प्रदान करने के लिए कार्रवाई करने के लिए कहें।

• सतत विकास के माध्यम से सभी के लिए समृद्धि प्राप्त करने के लिए एसडीजी की उपलब्धि में तेजी लाने की प्रतिबद्धता।

*****